P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-12* March- 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में उच्च शिक्षा के गुणवत्ता की चिंताएँ

Concerns about the Quality of Higher Education in India

Paper Submission: 20/03/2020, Date of Acceptance: 28/03/2020, Date of Publication:30/3/2020

रामकृत कुमार अरुण
सहायक प्रोफेसर,
वाणिज्य संकाय,
वीरांगना राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
महोबा, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

भारत में उच्च शिक्षा की प्रणाली एवं व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बनायी गयी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत निम्न तथ्यों का सामवेश होना अतिआवश्यक है। उच्च शिक्षा ज्ञानवर्धक हो एवं रोजगारपरक हो, सामाजिक मूल्यों पर आधारित हो, उच्च शिक्षा, मातृभाषा एवं अंग्रेजी भाषा दोनो में हो, उच्च शिक्षा सर्वांगीण विकास करने योग्य हो, उच्च शिक्षा तकनीकी एवं कौशल पर आधारित हो, उच्च शिक्षा में प्रबन्धशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास एवं सामाजिक मूल्यों के सन्दर्भ में पर्याप्त जानकारी से सम्बन्धित होना चाहिए। उच्च शिक्षा का अध्ययन व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए।

The system and system of higher education in India has been made by the British. Under the present education system, the collection of the following facts is very important. Higher education should be enlightening and employable, based on social values, higher education should be in both mother tongue and English language, higher education should be all round development, higher education should be based on technical and skills, management, economics, sociology in higher education, Should be related to adequate information in the context of political science, history and social values. The study of higher education should be based on the system.

मुख्य शब्द : उच्च शिक्षा, ज्ञानवर्धक, रोजगारपरक, पबन्धशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मातृभाषा, सर्वांगीण व्यक्तिगत, इन्जीनियरिंग, पॉलीटेक्निक, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, शारीरिक, मानसिक, बेरोजगारी, दुष्परिणाम, अस्थिरता, अभिनवकरण, दृष्टिकोण, मानवशक्ति, सामुदायिक, उत्पादकता, मनोबल।

Keywords : Higher Education, Enlightening, Employable, Management, Economics, Sociology, Political Science, Mother Tongue, All Round Personal, Engineering, Polytechnic, Central University, State University, Agricultural University, Physical, Mental, Unemployment, Side Effects, Instability, Innovation, Attitude, Manpower, Community , Productivity, Morale.

प्रस्तावना

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वर्तमान में चल रही शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इसमें उन सभी तत्वों को सम्मिलित करना पड़ेगा जो राष्ट्र–देश–समाज एवं व्यक्तियों का विकास करने योग्य हो। जैसे ज्ञानवर्द्धक एवं रोजगार परक, सामाजिक मूल्यों पर आधारित हो, तकनीकी एवं औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित हो। देश की जनसंख्या को रोजगार से जोड़ने वाली एवं पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने वाली होनी चाहिए। जल, जमीन, पहाड़, नदी एवं नालों के संरक्षण से सम्बन्धित होनी चाहिए। देश की जनसंख्या वृद्धि को रोकने से सम्बन्धित होनी चाहिए। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति के अन्दर प्रबन्ध, न्याय, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, पर्यावरण, सामाजिक मूल्यों एवं व्यक्ति विकास से सम्बन्धित एवं राष्ट्र प्रेम से सम्बन्धित पर्याप्त जानकारी मिलने योग्य होना चाहिए। यदि इन तत्वों का उच्च शिक्षा में समावेश कर दिया जाये तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति में राष्ट्र निर्माण की भावना एवं स्त्री–पुरुष में समानता एवं सामाजिक उत्थान के गुण विकसित हो जायेगें।

भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के प्रमुख कारण–

भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए प्रमुख तत्वों को शामिल किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा में सुधार करके रोजगारपरक बनाना

वर्तमान में चल रही उच्च शिक्षा व्यवस्था में जो त्रुटियां या जो कमियाँ हैं, उनको दूर करने का प्रयास होना चाहिए।

उच्च शिक्षा में बेरोजगारी की समस्या को दूर करना

इस समस्या को समाप्त करने के लिए सबसे पहले बेरोजगारी के बारे में जानकारी होना चाहिए।

बेरोजगारी का अर्थ

बेरोजगारी वह दशा है, जिसमें शारीरिक व मानसिक रुप से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को, जो कार्य करने की इच्छा रखता है, प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता।

ए0सी0 पीगू के अनुसार– ''एक व्यक्ति तभी बेरोजगार कहा जा सकता है, जब उसके पास कोई कार्य नहीं होता, किन्तु दूसरे वह कार्य करना चाहते हैं।''

लीग ऑफ नेशन्स के अनुसार ''एक बेकार व्यक्ति वह है, जो मजदूरी के लिए काम की तलाश में है और अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार कार्य पाने में असफल रहा हो।''

के0के0 गुप्ता के अनुसार :–''वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है, शारीरिक तथा माबनसिक दृष्टि से काम करने की क्षमता रखता है, किन्तु उसे कार्य नहीं मिलता अथवा काम से अलग होने के लिए बाध्य किया जाता है।''

शोध पत्र का उद्देश्य

भारत में उच्च शिक्षा में गुणवक्ता की चिन्ताँओं के विषय पर अध्ययन करने का मूल उद्देश्य यह है कि देश एवं समाज के सभी वर्गों के लोगों को यह जानना आवश्यक है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी उपयोगी है। कितनी ज्ञानवर्द्धक एवं रोजगारपरक है। इस वर्तमान समय के लिए उपयुक्त है, कि नहीं। देश की जनसंख्या का कल्याण करने योग्य है कि नहीं। शिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान करने वाली है कि नहीं। इन्हीं सभी तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है इस शोध पत्र से।

भारत में बेरोजगारी का अनुमान

भारत में बेरोजगारी के सम्बन्ध में पूर्णतः सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि विश्वसनीय आँकड़ों का अभाव है, किन्तु जो भी आँकड़े उपलब्ध हैं, इनके आधार पर देश में बेरोजगारी की स्थिति निम्नलिखित प्रकार दर्शायी गयी है।

भारत में बेरोजगारी की स्थिति (आँकड़े लाख में)

योजना	बेरोजगारों की बकाया संख्या	नव आगन्तुक	अतिरिक्त रोजगार	अन्तराल
प्रथम योजना	33	90	70	53
द्वितीय योजना	53	118	100	71
तृतीय योजना	71	170	145	96
तीनवर्षीय योजना	96	140	110	126
चतुर्थ योजना	126	230	185	171
पाँचवी योजना	171	270	220	221
छठी योजना	221	300	200	351
सातवीं योजना	351	240	280	391
आठवीं योजजना	391	–	–	–
नवीं योजना	378	–	–	–
दसवीं योजना	414	–	–	–

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि बेरोजगारी दूर करने के प्रयासों के बाद भी बेरोजगारी की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। प्रथम योजना के प्रारम्भ में 33 लाख बेरोजगार थे, जो बढ़कर दशवीं योजना के प्रारम्भ में 414 लाख हो गये। जनगणना 2001 के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों में 403.7 लाख व्यक्तियों के नाम बेरोजगार के रुप में पंजीकृत थे, लेकिन बेरोजगारों की वास्तविक संख्या 6 करोड़ (600 लाख) से ज्यादा होने का अनुमान है।

भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वालों में बेरोजगारी की समस्या

शिक्षित बेरोजगारी

नगरीय क्षेत्रों में मध्यमवर्गीय परिवारों से विशाल संख्या में अच्छे पढ़े–लिखे लोग प्रतिवर्ष रोजगार बाजार में आ रहे हैं, और उन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा है। वास्तविक अर्थों में बेरोजगारी की समस्या से हमारा आशय शिक्षित बेरोजगारी से होता है। हमारे देश में लाखों की संख्या में बेरोजगार जैसे– डॉक्टर, इन्जीनियर, टेक्नीशियन तथा स्नातक, विज्ञान वर्ग के स्नातक एवं स्नातकोत्तर, कला वर्ग स्नातक एवं स्नातकोत्तर, वाणिज्य वर्ग स्नातक एवं स्नातकोत्तर, प्रोफेशनल स्नातक एवं स्नातकोत्तर जैसे कि– एलएल0बी0 स्नातक, एलएल0एम0 स्नातकोत्तर, एम0बी0ए0 स्नातकोत्तर एवं आई0सी0डब्ल्यू0ए0 एवं सी0सी0ए0 स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं0 नेट पीएचडी की डिग्री प्राप्त देश के उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति बेरोजगार देश में इधर–उधर रोजगार के लिए भटक रहे हैं।

खुली बेरोजगारी का अर्थ

''जब व्यक्ति कार्य करने योग्य हैं और वे कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उनको कार्य नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति को खुली बेरोजगारी कहते हैं।''

भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी व्याप्त है। यहॉ लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित हैं, तकनीकी

योग्यता प्राप्त हैं, लेकिन काम करने काा अवसर नहीं मिल रहा है।

प्रोफेसर वरसिक (Worsick) के अनुसारः–''छिपी बेरोजगारी वह अवस्था है, जिसमें श्रम काा उपयोग अपव्ययपूर्ण रुप से हो रहा है।''

विकासशील या अविकसित देशों में विद्यमान छिपी हुई बेरोजगारी विकासशील देशों में पायी जाती है। क्योंकि इन देशों में जनसंख्या वृद्धि की गति तेज होती है। जबकि उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ता है।

विकसित व विकासशील देशों की छिपी बेरोजगादी की प्रकृति में अन्तर

विकसित देशों मे भी छिपी बेरोजगारी पायी जाती है। परन्तु उसकी प्रकृति में अन्तर होता है, विकसित देशों में यह अल्पकालिक होती है, जबकि विकासशील देशों में दीर्घकालीन होती है।

खुली बेरोजगारी

जो सामान्य मुख्य कसौटी की स्थिति में पायी जाती है। 1977–78 में 4.23 प्रतिशत कम होकर 1993–94 में 2.56 प्रतिशत हो गयी, परन्तु 1999–2000 में बढ़कर 2.81 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2009–2010 में यह घटकर 2.50 प्रतिशत पर आ गयी जो आर्थिक सुधारों के उपरान्त सबसे कम थी। 68वें दौर के अनुमान के अनुसार वर्ष 2011–12 के लिए 2.70 प्रतिशत रही।

भारत में बेरोजगारी का आकार

भारत में राष्ट्रीय न्यायदर्श सर्वेक्षण संगठन के आधर पर यह अनुमान लगाया गया कि चालू दैनिक स्थिति के आधार पर 1999–2000 में 265.8 लाख लोग बेरोजगार थे, जबकि 1993–94 में इनकी संख्या 201.3 लाख थी। आर्थिक सुधारों से पूर्व 1983 में यह संख्या 217.6 लाख थी। वर्ष 2004–2005 में बेरोजगारी की संख्या बढ़कर 247.4 लाख हो गयी। देश में वर्ष 2009–2010 में 281 लाख तथा 2011–2012 में 247 लाख लोग बेरोजगार थे। इस तरह बेरोजगारी में 2004–2005 से 2011–2012 के बीच 100 लाख की कमी आई।

बेरोजगारी– एक गम्भीर समस्या अथवा बेरोजगारी के दुष्परिणाम

राष्ट्र के लिए बेरोजगारी की समस्या एक गम्भीर समस्या है। इस समय कुल पंजीकृत बेरोजगारों में 60 प्रतिशत बेरोजगार पढ़े–लिखे उच्च शिक्षा प्राप्त है। प्रत्येक सात बेरोजगारों में से एक स्त्री है। इसके दुष्परिणाम निम्नलिखित है। मानव शक्ति का अर्थ जाना, सामाजिक समस्याओं का जन्म, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सम्पन्नता में कमी, बेरोजगारी से सामाजिक, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सम्पन्नता में कमी, बेरोजगारी से सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए विलियम बेवरिज (पससपंउ ठमअमतंपहम) नें लिखा है कि ''बेरोजगार रखने के स्थान पर लोगों को गड्ढे में खुदवाकर वापस भरने के लिए नियुक्त करना ज्यादा अच्छा है।''

भारत में उच्च शिक्षा में बेरोजगारी के कारण

भारत में बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण हैं–

बढ़ती जनसंख्या, 1.64 प्रतिशत वार्षिक की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, हस्तकला एवं लघु उद्योगों की अवनति, त्रुटिपूर्ण नियोजन, मन्दपूँजी निर्माण गति, पर्यावरण एवं अभिनवकरण, विदेशों से भारतीयों का आगमन, दोषपूर्ण दृष्टिकोण, मजदूरी एवं उत्पादकता में अन्तर, रोजगार विहीन सम्वृद्धि।

भारत में उच्च शिक्षा में बेरोजगारी दूर करने के उपाय

जनसंख्या पर नियन्त्रण, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास, प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण, कृषि पर आधारित उद्योग धन्धों का विकास, गॉव में रोजगार उन्मूल धंधों का विकासपूर्ण क्षमता का उपयोग, जनशक्ति नियोजन, विनियोग दर में वृद्धि, गॉवों में बिजलीघरों की स्थापना, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना, रोजगार की राष्ट्रीय नीति पूर्व निश्चित करना, अधिक भारतीय मानवशक्ति, मानवशक्ति सेवा निर्माण करना, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन, औद्योगिक सेवाओं को मजबूत करना, प्रत्येक सामुदायिक विकासखण्ड में कम से कम एक रोजगार दफ्तर रखना।

भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षित बेरोजगारी कम करने के लिये सरकारी प्रयास

भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के लिये बेरोजगारी दूर करने के प्रयास में निम्न योजनाऐं लागू की गयी है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग खोलने पर सहायता, परिवहन सहायता, स्वयं रोजगार कार्यक्रम, इन्जीनियरिंग साहसी प्रोग्राम, ग्रामीण साहसी कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम।

शिक्षित बेरोजगारी कम करने के उपाय

शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, प्रशिक्षण संस्थानों में वृद्धि, सूचना देने वाले संस्थानों में वृद्धि, मनोबल में परिवर्तन, सरकारी सहायता।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की चिंताओं के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तनों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है।

1. पुरानी शिक्षा प्रणाली को वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने की जरूरत है।
2. उच्च शिक्षा प्रणाली लोगों को रोजगार प्रदान करने वाली होनी चाहिए एवं ज्ञानवर्द्धक एवं तकनीकी एवं कौशल से पूर्ण होनी चाहिए।
3. उच्च शिक्षा प्रणाली उद्योग–धंधो एवं प्रबन्ध शास्त्र, प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए।
4. उच्च शिक्षा प्रणाली आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, इतिहास, संवैधानिक, स्वास्थ्य, मानवीय मूल्य, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की पर्याप्त जानकारी, पर्यावरण संरक्षण की पर्याप्त जानकारी प्रदान करने वाली होनी चाहिए।
5. व्यक्तिगत विकास के साथ राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल कौशल विकास, इन सभी तत्वों का शिक्षा व्यवस्था से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होनी चाहिए।
6. उच्च शिक्षा के माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र का विकास होना चाहिए। हर क्षेत्र एवं हर समाज से विकास होना चाहिए। विकसित क्षेत्र हो अथवा अल्प विकसित

क्षेत्र हो, हर क्षेत्र का सामान्य रुप से विकास होना चाहिए।

7. उच्च शिक्षा में प्रबन्ध सूचना प्रणाली एवं आधुनिक संचार प्रणालियों का समावेश होना चाहिए। जिससे सही तथ्यपरक सूचनाएँ प्राप्त हो सके एवं उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाये एवं उच्च शिक्षा को समाज के लिए महत्वपूर्ण बनाया जा सके।

सुझाव

वर्तमान में शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा प्रणाली ज्ञानवर्धक के साथ–साथ रोजगारपरक होनी चाहिए। तकनीकी ज्ञान से पूर्ण होनी चाहिए। हर वर्ग एवं हर समाज का उत्थान एवं कल्याणकारी होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक वर्ग शहरी एवं ग्रामीण सभी के सर्वांगीण विकास के लिये होना चाहिए। देश की शिक्षा व्यवस्था मातृभाषा में होने के कारण मातृभाषा की समझ प्रत्येक बच्चे में ज्यादा होती है, विदेशी भाषा की तुलना में। इसके बाद माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में मातृभाषा का अत्याधिक महत्वपूर्ण योगदान होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने में एवं प्रत्येक छात्र/छात्रा का सर्वांगीण विकास होगा। जैसे कि– आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, अपना व्यक्तिगत विकास करने एवं अपने गॉव,शहर, जिला,राज्य एवं देश का आर्थिक सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास करने में उच्च शिक्षा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। देश का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा। हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति का विकास करने में समझ होनी चाहिए। उच्च शिक्षा व्यवस्था देश के प्रत्येक क्षेत्र में समान रुप से होनी चाहिए, हर क्षेत्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा जैसे महाविद्यालय एवं राज्य विश्वविद्यालय एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं तकनीकी कालेज, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्जीनियरिंग, पॉलीटेक्निक, इन सभी शिक्षण संस्थान का पूरे देश में समान रुप में व्यवस्था होनी चाहिए। उच्च शिक्षा की व्यवस्था देश के प्रत्येक क्षेत्र में समान रुप से होनी चाहिए। जैसे कि शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र, चाहे पिछड़ा क्षेत्र, चाहे पहाड़ी इलाका हो, हर क्षेत्र से सम्बन्धित कालेज, महाविद्यालय एवं राज्य विश्वविद्यालय एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने चाहिए, पर्याप्त संख्या में मेडिकल कालेज एवं तकनीकी इन्जीनियरिंग एवं औद्योगिक कालेज जैसे कि पॉलीटेक्निक एवं आई0टी0आई0, एम0बी0ए0, बी0बी0ए0 आदि सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान होने चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References List)

व्यावसायिक पर्यावरण– साहित्य भवन प्रकाशन– आगरा ISBN – 978-93-5173-632-5

व्यावसायिक पर्यावरण– एसवीपीडी पब्लिगिंग हाउस– आगरा

संपादकीय दैनिक जागरण– सोमवार– 9 दिसम्बर 2019 मातृभाषा में हो प्रारम्भिक शिक्षा

आज दैनिक पेपर– मंगलवार 7 जनवरी 2020

प्रशिक्षित श्रमवल की आवश्यकता– संपादकीय

आज दैनिक समाचार पत्र – 5 फरवरी– बुधवार– 2020 शिक्षा को उद्योग से जोड़ेगी सरकार।

योजना– फरवरी 2020– शिक्षा में नर्वाचार (केन्द्र सरकार प्रकाशन) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

Lucent's सामान्य ज्ञान लेखक– सुनील कुमार सिंह स्नबदमजष् प्रकाशन पटना

योजना–दिसम्बर2019–भारत में चुनौतिया और अवसर,केन्द्र सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

मानव संसाधन प्रबन्ध–लेखकगण– डॉ0 चतुर्भुज मामोरिया, डॉ0 कामेश्वर पण्डित, प्रीति रैना, साहित्य भवन प्रकाशन आगरा

करेन्ट अफेयर्स (वार्षिकांक 2020)

उपकार सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन (लेखकगण डॉ0 आर0सी0 जैन एवं सूर्य नारायरण पाण्डेय– उपकार प्रकाशन आगरा– 2